Statement

State-wise No. of Districts of North-Eastern Region, including Assam, in which Navodaya Vidyalayas have been Sanctioned

Arunachal Pradesh	07
Assam	15
Manipur	08
Meghalaya	06
Mizoram	03
Nagaland	04
Tripura	03
TOTAL:	46

इस्पात के निर्यात हेतु योजनायें

*184. **श्री अजीत जोगी:** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी पांच वर्षों के दौरान इस्पात के निर्यात हेतु उनके मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्धारित उत्पादन लक्ष्य में कमी को गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता से पूरा किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अनुसंधान और विकास के संबंध में क्या-क्या कार्यक्रम शुरू किये गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) इस्पात मंत्रालय इस्पात के निर्यात में मददगार के रूप में कार्य करता है क्योंकि वर्तमान आयात-निर्यात नीति में इस प्रकार का निर्यात स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति है। इस्पात मंत्रालय ने सन् 2001-2002 तक 60 लाख टन इस्पात का निर्यात करने का अनुमान लगाया है। जबकि 1994-95 में 13 लाख टन इस्पात का निर्यात किया गया था।

(ख) और (ग) इस्पात की मांग (निर्यात के लिए मांग सहित) 200 लाख टन के वर्तमान स्तर से 2001-2002 में बढ़कर 370 लाख टन होने की संभावना है। चूंकि सरकारी क्षेत्र में कोई नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः मांग में इस वृद्धि को निजी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता सृजित करके और सरकारी क्षेत्र के मौजूदा इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार करके पूरा किया जाएगा। निजी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने की सुविधा के लिए तथा इसे प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने भी विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) लोहा और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकालना।

(2) लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट देना।

(3) विदेशी निवेश के उद्देश्य से लोहा और इस्पात को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करना।

(4) लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त करना।

(5) पूंजीगत सामान के आयात शुल्क में कमी करना, और

(6) आयात-निर्यात नीति का उदारीकरण।

17 प्रमुख परियोजनाओं जिनकी विक्रेय इस्पात की क्षमता लगभग 92 लाख टन है और जिनमें लगभग 16234 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, को वित्तीय संस्थानों ने मंजूरी दे दी है। लगभग 54.7 लाख टन क्षमता और लगभग 10709 करोड़ रुपए के निवेश की आठ और परियोजनाओं का इस समय मूल्यांकन किया जा रहा है।

(घ) एकीकृत इस्पात संयंत्र उर्जा संरक्षण, धमन भट्टी उत्पादकता, क्वालिटी नियंत्रण, सिन्टर संयंत्र की उत्पादकता आदि क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य कर रहे हैं।

Closure of Aligarh University

*185. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Aligarh University was closed for an indefinite period in November, 1995;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what steps are being taken by Government for maintaining peace and

educational ambience in the University?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) and (b) Aligarh Muslim University (AMU) was closed sine die on November 15, 1995 following disruption of the functioning of the University, violence, arson and damage to property by a section of students and some others.

(c) The corrective measures being contemplated by the University authorities include identification and eviction of criminal elements and unauthorised occupants from hostels, disciplinary action against persons involved in the incidents leading to closure of the University, weeding out of undesirable elements, etc.

Results of Kendriya Vidyalaya Students

*186. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of over-all and subject-wise results of students of Kendriya Vidyalayas at the CBSE Examinations during the preceding three academic years as compared to students of non-Kendriya Vidyalayas put together;

(b) the details of toppers or position-holders in different subjects during the said period belonging to Kendriya Vidyalayas and non-Kendriya Vidyalayas;

(c) whether there has been a progressive decline in quality or results of Kendriya Vidyalaya children; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) A Statement is laid on the Table of the House. (*See* below)

(b) The Central Board of Secondary Education does not declare the position holders. However, 0.1% subject toppers are issued merit certificates. Number of students from Kendriya Vidyalayas and total number in C.B.S.E. securing merit certificates during the last 3 years are given below:—

	Class-X		Class-XII	
Year	KVs.	CBSE	KVs.	CBSE
1993	332	1845	173	1309
1994	272	1805	263	2253
1995	297	2136	193	1293

(c) and (d) The results of both Class X and Class XII examinations of Kendriya Vidyalayas for the past three years have remained substantially the same except during 1995 when a decline was noticed in the Class X performance. This is mainly due to a change in the examination pattern prescribed by Central Board of Secondary Education.